भारत – यमन संबंध

भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाने में यमन को सक्रिय समर्थन प्रदान किया था। भारत 1962 में यमन अरब रिपब्लिक (वाई ए आर) और 1967 में यमन लोकतांत्रिक गणराज्य (पी डी आर वाई) को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। वर्ष 1990 में, वाई ए आर और पी डी आर वाई यमन गणराज्य में आमेलित हो गए थे।

वर्ष 2011 में अरब उत्थान के परिणामस्वरूप पूर्व राष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया और जी सी सी द्वारा प्रायोजित एक करार के फलस्वरूप नए राष्ट्रपति अब्दो रब्बू मन्सूर हैदी के अंतर्गत दो वर्ष के लिए अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ट्रांजीशन अवधि के पूरा होने तक राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नए यमन पर विचार करने के लिए गठित राष्ट्रीय वार्ता सम्मेलन (या एन डी सी) के परिणामों के आधार पर नया संविधान तैयार हो रहा था। तथापि, जनवरी 2015 में कुछ आंतरिक टकरावों के बाद राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तथा इसके शीघ्र बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, जिससे सरकार एवं देश अनिश्चितता के दलदल में फंस गया। संयुक्त राष्ट्र की सहायता से, राजनीतिक दलों एवं गुटों के बीच हुए विभिन्न करारों में परिकल्पना के अनुसार, एक नई सरकार के गठन का प्रयास किया गया है जो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। अपने त्यागपत्र के लगभग एक माह बाद राष्ट्रपति हैदी साना छोड़कर अदेन चले गए जहां उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। इससे खराब सुरक्षा स्थिति और बिगड़ गई। हैदी को राष्ट्रपति के रूप में बहाल करने के उद्देश्य से 26 मार्च, 2015 को गठबंधन बलों के एक गुट द्वारा यमन में हवाई बमबारी शुरू होने तक गतिरोध जारी था। ऑपरेशन जारी है।

यमन और इसकी जनता की सोच भारत की सोच से मेल खाती है और इसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है।

निमंत्रण प्राप्त होने पर, भारत ने अप्रैल 2012 में "फ्रैण्ड्स ऑफ यमन ग्रुप" को ज्वाइन किया ताकि देश को ट्रांजीशन फेज में मदद की जा सके।

2. राजनीतिक :

यमन के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं जब यमनीज रोमनों के साथ जुड़े हुए थे। 19वीं और 20वीं सदी में, अदन, मोचा और कामरान द्वीपसमूह हज यात्रियों के लिए ट्रांजिट अथवा ट्रांसशिपमेंट का बिंदु बन गए थे। दक्षिणी यमन एक ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र था जो बॉम्बे प्रेसीडेंसी द्वारा शासित था जिसके दौरान एक भारतीय गैरीसन सेवा कर रहा था, जबकि रुपया आधिकारिक

मुद्रा थी। आजादी से पूर्व के भारत में, अदन कई प्रमुख भारतीयों के लिए एक पोर्ट ऑफ कॉल बन गया था, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पण्डित मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू ने वहां की यात्रा की थी।

भारत की आजादी की लड़ाई में विजय और यमन अरब रिपब्लिक तथा पीपुल्स डेमाक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन को मान्यता प्राप्त होने से उपनिवेश पश्चात काल में संबंधों की नींव पड़ी जो 1980 के दशक के दौरान गहरी होने लगी। यमन अन्य देशों के साथ-साथ इंडियन ओशियन रिम एसोशिएसन (आई ओ आर ए) का सदस्य है। यमन एक विस्तारित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन करता रहा है।

हाल ही के समय में, अधिकारी स्तर पर श्रृंखलाबद्ध द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन हुआ है। वर्ष 2013 में, संयुक्त आयोग की बैठक का 8वां सत्र नई दिल्ली में दिनांक 11-12 मार्च 2013 को आयोजित हुआ था। यमन के पक्ष का नेतृत्व योजना एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग उप मंत्री श्री अब्दुल अजीज अब्दुल गनी ने और भारतीय पक्ष का नेतृत्व पूर्व सचिव (पूर्व) श्री संजय सिंह ने किया। संयुक्त सचिव (खाड़ी) श्री मृदुल कुमार ने 21 और 22 नवंबर 2013 को यमन का दौरा किया और प्रथम उप मंत्री डॉ. अब्दुलकवी ए नोमान को 2 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य के भारतीय गेहूँ सौंपे और अन्य के साथ-साथ, योजना एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री मोहम्मद अल सईद अल सादी, उप विदेश मंत्री डॉ. अली हसन मुथाना, प्रथम उप व्यापार मंत्री श्री इकबाल बहादर के साथ बातचीत की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री वी एस सम्पत ने यमन का दौरा किया और चुनाव एवं जनमत संग्रह के लिए सर्वोच्च आयोग के अध्यक्ष अपने समक्ष जज श्री मोहम्मद हुसैन अल हाकिमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, साथ ही, यमन के राष्ट्रपति हैदी से भी मुलाकात की। तत्कालीन विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री सलीह हसन सुमिया ने मई 2013 में हैदराबाद का दौरा किया। भेल, भारत यमन में एक विद्युत संयंत्र स्थापित कर रहा है। जन स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री डॉ. अहमद अल अन्सी ने भारत के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए 4 से 7 जुलाई 2013 तक भारत का दौरा किया।

इससे पहले, यमन के तत्कालीन विदेश मंत्री डॉ. अबू बकर अल किरबी ने 11 से 15 नवंबर 2011 तक बंगलूरू में आई ओ आर ए मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी। नोबल पुरस्कार विजेता तवक्कुल कारमान ने आई सी सी आर के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल 2012 में भारत का दौरा किया था। अंतिम उच्च स्तरीय दौरा 1999 में हुआ जब राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने मार्च 1999 में और उप राष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत ने अक्टूबर 1999 में द्विपक्षीय विचार-विनिमय और वार्ता के लिए दौरे किए।

भारत में हिंद महासागर परिघि संघ के वर्ष 2014 के निम्नलिखित कार्यक्रमों में यमन की ओर से अच्छा भागीदारी रही, अर्थात (i) 17 से 19 सितंबर, 2014 के दौरान हैदराबाद में आयोजित महिला सशक्तीकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यशाला; (ii) 5 से 7 सितंबर 2014 के दौरान कोचीन में आयोजित हिंद महासागर संवाद; और (iii) 13 और 14 अक्टूबर, 2015 को समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा पर आयोजित विशेषज्ञों की आई ओ आर ए बैठक।

अनेक द्विपक्षीय करार किए गए हैं जो आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग, वायु सेवा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, सांस्कृतिक, द्विपक्षीय निवेश संवर्धन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, तेल एवं गैस उद्योग तथा शैक्षिक आदान-प्रदान में सहयोग / करार से जुड़े हुए हैं।

अदन विश्वविद्यालय ने रुड़की विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सहयोग स्थापित किया था। कई भारतीय प्राध्यापकों ने साना और अदन विश्वविद्यालयों में संकाय स्थापित किए हैं और अलग-अलग विभागों की अध्यक्षता की है।

दो अग्रणी थिंक टैंक, इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स (आई सी डब्ल्यू ए) और शेबा सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज ने विशेषज्ञों और विश्लेषकों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने तथा पारस्परिक हित के विषयों पर सेमीनारों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए भागीदारी विकसित करने के लिए अप्रैल 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने यमन में एक आई टी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है जिसे यमन की ओर से स्वीकार कर लिया गया है।

यमन में स्थिरता आने के बाद ही द्विपक्षीय संबंधों में कोई और विकास हो सकता है।

3 वाणिज्यिक :

बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1950 में अदन में एक शाखा खोली थी जिसे 1970 में नेशनल बैंक ऑफ सदर्न यमन (अब नेशनल बैंक ऑफ यमन) में निगमित कर लिया गया है।

भारत यमनी सामानों का चीन और थाईलैण्ड के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक है जबकि भारत यमन के लिए संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैण्ड, नीदरलैण्ड और चीन के बाद पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है (सांख्यिकी 2012)। वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार 1.53 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

भारत यमन को खनिज तेल और उनके डिस्टिलेशन उत्पाद, अनाज, चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी, औषधीय उत्पाद, पहनने और ओढ़ने के वस्त्र, चाय, चावल, गेहूँ, अनाज, मसाले, तम्बाकू, मांस और मांस से बने उत्पाद, हाथ से चलाए जाने वाले औजार, रासायनिक पदार्थों का निर्यात करता है। दूसरी ओर, भारत यमन से खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके डिस्टिलेशन के उत्पाद, शीशा और उससे बनी वस्तुएं, कच्ची खाल और चमड़ा (फर स्किन को छोड़कर), चमड़ा और चूना पत्थर का आयात करता है।

यमन के फार्मा आयातों में भारत दूसरे नम्बर पर है, जिसमें इस देश के बाजार में अन्य के साथ-साथ, रैनबैक्सी, सिप्ला, सन फार्मा, एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड, कैडिला, वोकार्ट, ग्लेनमार्क, कोपरान लेबोरेटरीज लिमिटेड, ऑर्किड, मेडली और बायोकॉन सक्रिय हैं।

भारत ने यमन के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग में गहरी रुचि दर्शाई है। विगत समय में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस और मंगलौर रिफाइनरीज ने यमन से कच्चा तेल आयात किया है। एक कंसोर्टियम में रिलायंस, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा आयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन को यमन में आयल ब्लॉक आबंटित किए गए हैं।

मेना और खाड़ी के अपोलो अस्पतालों के मुखिया डॉ. वालिद एम अल बकीली की अध्यक्षता में एक सी आई आई प्रतिनिधिमंडल तथा चार अन्य सदस्यों ने 9 से 12 मार्च 2014 तक यमन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने साना, अदन और मुकल्ला में सेमीनारों का आयोजन किया, और साथ ही, कृषि एवं सिंचाई मंत्री इंजीनियर फरीद अहमद मुजावर, योजना एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग उप मंत्री डॉ. मुत्तहर अल अब्बासी तथा अन्य के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। फरवरी 2013 में, नागार्जुन समूह के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए दौरा किया; वारी ग्रुप के एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोलर वॉटर पंपिंग स्टेशन की स्थापना के लिए दौरा किया। एक सेमीनार के आयोजन के अवसर पर, अन्य के साथ-साथ टाटा, भेल, सन फार्मा और वारी ग्रुप के प्रतिनिधियों ने भाषण दिया। यमन भारत व्यावसायिक परिषद के अध्यक्ष ने मुम्बई में मार्च 2013 में इंडियन इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने 8 से 10 दिसंबर 2013 तक सना'आ का दौरा किया। सबसे कम विकसित देशों के लिए भारत की ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रिफरेन्स स्कीम (डी एफ टी पी) 2 अप्रैल 2013 को अधिसूचित की गई थी। दो व्यक्ति, नामत: यमनी - भारतीय व्यावसायिक परिषद तथा ईएमार सीमेंट एंड सेल्स कंपनी के अध्यक्ष श्री अहमद सलेम सम्माख और कंपनी के उप प्रबंधक श्री ऐमान एराब 26-27 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में चौथी भारत - अरब भागीदारी शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए भारत आए।

फेडरेशन ऑफ दी यमनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ वाई सी सी आई) के सहयोग से दूतावास ने सना'आ में 28 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के लिए एक सेमीनार का आयोजन किया जिसमें अच्छी-खासी उपस्थिति रही। यमन की अलग-अलग कंपनियों के 43 उद्यमियों और कार्यकारी अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भेल ने भी अपने वैश्विक कार्यक्रमों के संबंध में 7 मिनट की प्रस्तुति दी।

सितंबर माह के आरंभ में, फोर्टिस अस्पताल, बंगलौर के तीन प्रख्यात विशेषज्ञों ने सना'आ में अल-थावरा अस्पताल (सरकार के स्वामित्व वाले) का दौरा किया और बड़ी संख्या में यमन के मरीजों की चिकित्सा जांच और ऑपरेशन किए ये तीन डॉक्टर यूरोलोजिस्ट, गेस्ट्रोएंटरोलोलिस्ट और न्यूरोलोजिस्ट थे।

भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में एक उपक्रम, वापकोस लिमिटेड के पक्ष में यमन में निम्नलिखित परियोजनाएं अधिनिर्णीत की गई हैं :

(क) हैडरामाउट गवर्नोरेट में अब्दुल्ला गरीब रोड सेक्शन के लिए सड़क निर्माण पर्यवेक्षण हेतु परामर्श सेवा (यमन के लोक निर्माण एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ)।

(ख) अबयान गवर्नोरेट में हनाड वियर एवं हलाड लेफ्ट मेन कैनाल के पुनर्निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु परामर्श सेवा (यमन के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के साथ)।

यमन में आंतरिक घटनाओं के कारण बढ़ती आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को आघात लगा है। दो परियोजनाएं, एक सऊदी द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले 211.41 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के अमरान - अडेन राजमार्ग का निर्माण और दूसरी धमार एवं अडेन के बीच 62 मिलियन अमरीकी डॉलर की विद्युत पारेषण लाइन, जहां आबु धाबी का आंशिक वित्त पोषण शामिल है, प्रभावित हुई हैं।

4. आई टी ई सी **/** आई सी सी आर छात्रवृत्तियां :

भारत स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल कार्यक्रमों में अध्ययन के लिए आई सी सी आर के तत्वावधान में विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत यमन को क्षमता निर्माण के लिए सिविलियन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

मंत्रालय ने वर्ष 2013-2014 के लिए मांगे गए 110 स्लॉटों की तुलना में 108 स्लॉट स्वीकृत किए थे। वर्ष 2013-14 में, यमनी नागरिकों द्वारा 103 आई टी ई सी स्लॉटों का उपयोग किया गया; पांच आवेदक व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से नहीं आ सके। वर्ष 2014-15 के लिए, मंत्रालय ने यमन के लिए 80 स्लॉट आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, आई सी सी आर ने वर्ष 2014-15 के लिए यमनी छात्रों के लिए 52 स्लॉट आवंटित किए थे और 50 अभ्यर्थियों ने इस छात्रवृत्ति योजना का उपयोग किया है।

2015-16 के लिए आई सी सी आर छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। यमन में सुरक्षा की निरंतर कठिन स्थिति के बावजूद इस मिशन को आबंटित 58 स्लॉटों में से 43 स्लॉटों का उपयोग किया गया तथा अप्रैल 2015 में स्टाफ की संख्या घटाकर मिशन को जिबोटी में शिफ्ट किया गया।

2015-16 में यमन में विद्यमान स्थिति की वजह से अब तक आई टी ई सी के तहत एक भी छात्रवृत्ति की पेशकश नहीं की गई है।

5. सांस्कृतिक **:**

एक नया सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम विचाराधीन है। आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक जत्थों ने यमन के अलग-अलग भागों में नियमित रूप से प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें अंतिम प्रस्तुति राजस्थानी लोक सांस्कृतिक जत्थे द्वारा साना, अदन और तैज में दी गई। टैगोर की 150वीं जयंती की स्मृति में नवंबर 2011 और जनवरी 2012 में साना में दो विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था।

6. भारतीय समुदाय **:**

भारत और यमन के बीच कई सदियों से स्पंदनशील संबंधों का अच्छा मेलजोल है। ब्रिटिश शासन में अदन 1839 से 1939 तक बॉम्बे प्रेसीडेंसी द्वारा अभिशासित था जिसके दौरान अदन में 2000 भारतीय सैनिकों की एक गैरीसन तैनात थी और 1855 से अदन तथा बॉम्बे के बीच एक नियमित स्टीमर सेवा चलती थी। 1950 के दशक के मध्य तक, कई भारतीय अर्थात् हिंदू, मुस्लिम और पारसियों ने अदन में निवास किया था। इसके परिणामस्वरूप हिंदू, जैन और पारसी समुदायों के लिए समृद्ध भारतीय विरासत के मंदिरों की स्थापना हुई, ऐसे 10 मंदिरों में से एक का अभी भी सक्रिय रूप से संरक्षण किया जा रहा है। आजादी के बाद से, कई भारतीयों ने यमनी नागरिकता ले ली है- यमनी समुदायों में विवाह कर लिया है। उनमें से पर्याप्त आबादी भारतीय रीति-रिवाजों और परंपराओं का अनुसरण करती है।

मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टरों ने होदैदाह, सना'आ, तैज और अदन में केंद्र खोले हैं। सबसे पहले केंद्र, एक कुष्ठ केंद्र, का उद्घाटन होदैदाह में 1973 में मदर टेरेसा द्वारा किया गया था।

यमन में हैदरामाउट राज्य (प्रांत) के डेक्कन (भारत) के साथ मजबूत संबंध थे और अभी भी हैं। हैदरामाउट के सैयद परिवारों ने अस्पताल और अरबी संगठन स्थापित किए थे और हैदराबाद के निजाम ने इस क्षेत्र के यमनियों को सैनिकों के रूप में नियुक्त किया था जो अपनी अत्यधिक वीरता और पूर्ण स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते थे।

सीमापार के संपर्कों के फलस्वरूप यमनी मूल के लगभग 300,000 भारतीय मुख्यत: हैदराबाद में तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के इसके निकटवर्ती शहरों में हैं। इसी प्रकार भारतीय मूल के लगभग 200,000 व्यक्तियों का समुदाय अदन, हैदरामाउट, होदैदाह, तैज और साना में है।

साना, अदन, तैज और होदैदाह में भारतीय संघ मौजूद हैं और सक्रिय रूप से सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अदन का भारतीय संघ सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासन काल में हुई थी।

मार्च 2015 में गठबंधन सेना द्वारा हवाई हमलों की शुरूआत के बाद यमन में राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति अनिश्चित हो गई है। स्थिति में सुधार होने की संभावना तभी है जब यमन में विभिन्न दलों के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता होगा। अत: ऑपरेशन राहत के तहत भारत सरकार ने यमन से भारी संख्या में भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया है।

स्वयं भारतीय दूतावास, साना को अस्थाई तौर पर 14 अप्रैल, 2015 से जिबोटी में शिफ्ट कर दिया गया है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, साना की वेबसाइट :
www.eoisanaa.org

भारतीय दूतावास, साना का फेसबुक पेज :
https://www.facebook.com/EmbassyofIndiainSanaaYemen/

भारतीय दूतावास, साना का ट्विटर :
https://twitter.com/indiainyemen

*****

जनवरी**, 2016**